

सम्पादकीय

फजीहत की पेशन

पिछले दिनों हरियाणा की वह घटना राष्ट्रीय मीडिया में सुखियां बनी, जिसमें रोहतक के 102 वर्षीय दुलीचंद ने वश्वावस्था पेंशन बंद होने पर रचनात्मक तरीके से विरोध करके सरकारी तंत्र जगाया। उन्होंने बाकायदा बैंड-बाजे के साथ बारात निकाली। वे हाथ में तख्ती लिये थे कि 'तुम्हारा फूफा अभी जिंदा है'। दरअसल, दुलीचंद कागजों में जीवित नहीं दिखाये गये थे। वे समाज कल्याण विभाग के दफतरों के चक्कर काटते थक गये। जब कोई राह न दिखी तो रचनात्मक विरोध का यह तरीका अपनाया। निस्संदेह, इस घटनाक्रम ने उन्नींदे तंत्र को जगाया। न केवल समाज कल्याण विभाग हरकत में आया बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के जरिये वश्वावस्था पेंशन से वंचित लोगों का दुख-दर्द सुना। यहां तक कि पेंशन से वंचित एक महिला को न केवल पेंशन तुरंत शुरू होने का आश्वासन दिया बल्कि एक माह की पेंशन अपनी जेब से देकर संवेदनशील शासक का उदाहरण भी दिया। सवाल ये है कि समाज कल्याण विभाग ऐसी पहल क्यों नहीं करता? यह जानते हुए भी कि उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक शैथिल्य व आय के संसाधन न होने पर बुर्जुआ वैसे ही परेशान रहते हैं। तो पेंशन के गिने-चुने वैसे तो कम से कम सही समय पर मिल जायें। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जीवित लोगों को खुद को जिंदा दिखाने के लिये दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं? सवाल यह भी कि पेंशन बंदी किस आधार पर की जाती है जबकि व्यक्ति जीवित रहता है? वैसे भी साल में एक बार पेंशनरों को संबंधित विभाग में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र बाकायदा देना ही पड़ता है। सवाल यह भी कि क्यों ऐसे दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना ही किसी की पेंशन रोक देते हैं। सही मायनों में असहाय बुढापे में पेंशन एक प्राणवायु की तरह होती है। वैसे तो इतने पैसे में महंगाई के जमाने में आता ही क्या है लेकिन परिस्थितियों के चलते उसके भी खास मायने होते हैं। निस्संदेह, पेंशन जैसे विभाग मौजूदा दौर में एक पोल खाता डिपार्टमेंट बन गये हैं। किसी को जीवित रहते मशक्त क्षोषित करने की खबर आती है, तो किसी के परिवार को वर्षों तक मरने के बाद भी पेंशन मिलती रहती है। पेंशन वितरण में कई तरह के घपले सामने आते रहते हैं। जो दर्शाता है कि संबंधित विभाग जिम्मेदारी व संवेदनशील ढंग से कार्य नहीं करता है। निस्संदेह, इस विभाग के लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे बुर्जुआं से कैसे व्यवहार करें। उनके मामलों के निस्तारण में बेहद संवेदनशीलता दिखाएं। यदि विभाग के लोग जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो दुलीचंद जैसे प्रकरण सामने नहीं आयेंगे। वहीं यह भी विडंबना है कि जरूरतमंद वर्ग की पेंशन को एक राजनीतिक एजेंडे की तरह दर्शाया जाता है। चुनाव से पहले कई राजनीतिक दल लंबी-चौड़ी हाँकते हैं कि हम सत्ता में आये तो इतनी पेंशन दे देंगे। जबकि वे सरकार के सीमित संसाधनों को जानते हैं।



हेन्द्र और राज्य सरकार पिछले लम्बे सरसे से स्वच्छता अभियान के बड़े परोड़े आयोजन और दिखावा करते आ रहे हैं। ठीक इसके विपरीत जिस तरह ने कचरे की अनदेखी और लापरवाही के कारण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिस तरह से राज्यों एवं स्थानीय निकायों ने अपर जुर्माना ठोक रहा है वह इस बॉट ना प्रतीक है कि सरकारें और स्थानीय निकाय प्रबंधन कचरे को लेकर गम्भीर चुनौती है। ताजे उदाहरण में राजस्थान सरकार पर 3500 करोड़ के जुर्माने के साथ इसके कुछ और पहले वह बंगाल सरकार पर सीधे शोधन संयंत्रों को नहीं तरह संचालित न करने के कारण 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है। एनजीटी उत्तर प्रदेश सरकार ने कचरे का उचित प्रबंधन न कर जाने के कारण पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 120 करोड़ रुपये की राशि निर्मान करने का निर्देश दे चुका है। बूढ़े के निरस्तारण के लिए जारी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण गाइड लाइन और दिशा निर्देशों की कदम कदम पर अनदेखी की जा रही है लेकिन सरकार और निकाय प्रबंधन सो रहे हैं। देखा जाए तो प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर पृथ्वी को हम कचरे के ढेर एवं परिवर्तित करते जा रहे हैं। नदी, नीली, तालाब और महासागरों को हमने बूढ़ाघर बना दिया है। पहाड़ की गाड़ियों, बुरायालों और हिमालय में भी हम कड़े का जहर घोलने से पीछे नहीं रहे। इसी कारण जल और थल प्रदूषित हो रहे हैं। आसमान (हवा) को जहरीली गोंगों ने प्रदूषित कर दिया है। ये गैंगे उद्योगों और परिवहन माध्यमों सहित एसी जैसे विभिन्न उत्पादों से निकलती हैं, लेकिन इसमें बड़ा योगदान इंसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर डंप किए जाने के कारण पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में ही इसे जला दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय कचरे की संग्रहीतीक से प्रबंधन करने की व्यवस्था करने वाले नगर निकाय और हम सरकार हैं। जिस करण देश में विभिन्न बीमारियां जन्म ले रही हैं।

A photograph showing a large pile of trash and debris, including plastic bags and containers, scattered across a field or roadside. In the background, there are trees and some buildings under a cloudy sky.

फीसदी का इजाफा हुआ है। देखा गए तो निर्माण कार्य, वाहनों से निकले गए, कचरा और पराली प्रदूषण की व्यवस्था बेचते हैं। अब प्रदूषण फैलाने ले कारकों में होटल, रेस्टोरेंट, टल्स, बैंकवेट हॉल भी नेशनल ग्रीन ब्यूनल (एनजीटी) ने शामिल कर दिया है। द्विव्यूनल के मुताबिक मानकों विपरीत निर्माण समेत प्रदूषण फैलाने तमाम गतिविधियां इनमें होती हैं। एक दूसरे पर रोक लगाने के लिए स्थानीय कायाएँ और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण डॉड को निर्देश है। जारी निर्देशों के द्वारा होटल, मोटर हॉल में सीवेज ट्रीटमेंट संट लगाना अनिवार्य है। 20 या उनसे कम कमरों वाले होटल, 100 या 100 मीटर क्षेत्रफल वाले बैंकवेट हॉल तक 36 लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट और ईटीपी लगाना होगा। ईटीपी से नियंत्रण वाले डिस्चार्ज में पर्यावरणीय नियंत्रणों का पालन करना होगा। असकी जांच संबंधित विभाग निर्धारित लग—अलग समय पर करेंगे। लेकिन उनका शायद रक्ती भर अनुपालन नहीं होगा जा रहा है। यदि स्वच्छता अभियान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उत्तर रहा है तो इसके लिए जितनी

लगाया, क्योंकि राज्य के कुछ शहरों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को नदियों में उड़ेला जा रहा था, तो कुछ में कचरे का निस्तारण ढंग से नहीं किया जा रहा था। इसके पहले एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में नाकामी के चलते लगाया था। हाल के दिनों में एनजीटी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कारण कई राज्य सरकारों अथवा उनके नगर निकायों के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रखा है। यह सख्ती यही बताती है कि राज्य सरकारें, उनके नगर निकाय और प्रदूषण की रोकथाम करने वाले विभाग अपने दायित्वों का सही तरह निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति पूरे देश और यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। जबकि करीब दो सप्ताह पहले एनजीटी ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए अपना असंतोष प्रकट किया था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार और

नगर निगम के बीच आरोप-प्रत्यारोप तो जारी रहता है, लेकिन इसके कोई आसार नहीं दिखते कि देश की राजधानी को कचरे के पहाड़ों से छुटकारा मिलेगा। स्वच्छता अभियान जारी रहने के बावजूद कचरा निस्तारण में हीलाहवाली और कारखानों से निकलने वाले विषाक्त पानी को नदियों में छोड़ना एक ऐसी समस्या है, जिसका कोई ठोस समाधान होता नहीं दिखता। इसमें संदेह है कि राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने से यह समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि न तो कचरे के निस्तारण की कोई कारगर व्यवस्था बन पा रही है और न ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि सीवेज शोधन संयंत्र सही तरह संचालित हों। यदि स्वच्छता अभियान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उत्तर पा रहा है तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार राज्य सरकारें और उनके नगर निकाय हैं, उतना ही लोगों की यह मानसिकता कि कचरे का निस्तारण करना केवल सरकारों की जिम्मेदारी है। यदि गंदगी और प्रदूषण से लड़ना है तो आम नागरिकों से लेकर नगर निकायों को अपनी जिम्मेदारी का सही तरह निर्वाह करना होगा। — **प्रेम शर्मा**

आज का राशिफल

मेष :- उच्चस्तरीय लोगों के सानिध्य से मनोबल मजबूत होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। शासन-सत्ता से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी।

वृषभ :- अत्यधिक कर्जभार से मन परेशान होगा। कुछ नयी आकांक्षाएं मन को उद्घेलित करेंगी। रोजगार में व्यस्तता संभव। अत्यधिक पारिवारिक वृत्तियां देखते हुए भविष्य की चिंता बढ़ेगी फिर भी कुछ नये आसार

अस्पताल विभाग



A photograph showing a woman with glasses and a green shawl holding a baby wrapped in a purple and white striped cloth. Another woman in a red and yellow sari is visible in the background.

नहीं होना चाहिए। यदि शहरों में बड़े अस्पताल बनते हैं तो ग्रामीणों को यातायात व रहने-खाने पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। निस्संदेह, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का आदि आकार है। सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीणों को निकट के करबों व शहरों में गुणवत्ता का उपचार मिल सके। साथ ही वे फर्जी डॉक्टरों व नीम-हकीमों के चंगुल से मुक्त हो सकेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य तंत्र भ्रष्टाचार से मुक्त हो और केंद्र व राज्य स्वास्थ्य बजट में लगातार वृद्धि करते रहें। वर्हीं यह बात शिद्दत से महसूस की जाती रही है कि ग्रामों व छोटे शहरों में भी विशेषज्ञता का उपचार उपलब्ध हो। जब सरकारें चिकित्सा सेवाओं पर पर्याप्त धन खर्च करती हैं तो मरीजों व उनके तीमारदारों की जेब पर खर्च का दबाव कम होता है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सूची में शामिल होती हैं लेकिन केंद्र सरकार

<p>केंद्र की नीतिया बहतर स्वास्थ्य वाओं के अनुकूल माहौल बना सकती। कोरोना संकट में केंद्र की प्रभावी नीतियों से बेहतर टीकाकरण के लक्ष्य सिल भी हुए। निस्संदेह, किसी भी एक कल्याणकारी राज्य की सफलता उत्तर शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं पर भर्त रखती है। कोरोना संकट में जी अस्पतालों ने मरीजों को जिस दूर उलटे उत्तर से मूँडा, उसको खेते हुए सरकारी चिकित्सा सेवा की उत्तर का बोध होता है। प्राइवेट अस्पतालों का विस्तार हो और उसमें जी निवेश को बढ़ावा मिले, लेकिन तुलन के लिये बेहतर सरकारी चिकित्सा सेवाओं का होना भी जरूरी। केवल स्वास्थ्य बीमा योजनाओं र निजी अस्पतालों के वर्चर्स्व से अ आदमी को राहत नहीं मिल कती। केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अपर पर जीडीपी के तीन फीसदी के स्वास्थ्य सेवा पर खर्च के पैमाने के क्षय को हकीकत बनाने के लिये अनादार प्रयास करने चाहिए।</p>	<p>मामलों में कठिनाइयां संभव। तामसिक विचारें पर नियंतप्ररखें।</p> <p>कर्क :- महत्वपूर्ण कार्य के प्रति समुचित साधन व्यवस्था के लिए मन केंद्रित होगा। नई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनेंगी किंतु समुचित साधन न होने से पूर्ति में अवरोध होगा। पुराने संबंधों के प्रगाढ़ता बढ़ेगी।</p> <p>सिंह :- सगे-संबंधियों के सहयोग से उत्साह का संचार होगा। किसी रचनात्मक कार्य के प्रति रुचि पैदा होगी। पुराने संबंधों के भावनात्मक स्मरण से मन भावुक होगा। राजकीय क्षेत्र कुछ परिवर्तन के आसार बनेंगे।</p> <p>कन्या :- आलस्य निजी महत्वपूर्ण दावितों की पूर्ति में बाधक होगा। मानसिक अवसाद व कार्य-पैशे में अरुचि से अर्थिक संकट की आशंका बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।</p>	<p>क कार्यों का बोझ से बोझिल होंगे। शिक्षा-प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी।</p> <p>मकर :- आर्थिक सबलता हेतु मन नई युक्तियों पर केंद्रित होगा। कोई अचल सम्पत्ति संबंधी तनाव मन को चिंतित करेगा। पुराने संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। जरूरी कायरे में कतई देरी न करें।</p> <p>कुंभ :- पारिवारिक दावितों की समय से पूर्ति हेतु प्रयत्नशील होंगे। अच्छी सोच का लाभ प्राप्त करेंगे। परिजनों के सुख-दुख के प्रति मन में चिंता होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रति चिंताएं समाप्त होंगी।</p> <p>मीन :- नये संबंधों के साथ आपकी सहज घुलसशीलता प्रशंसनीय है। कार्य को समयानुकूल पूर्ण करने का प्रयत्न करें। बिना वजह दूसरों की अलोचना न करें। आलस्य कर्तई न करें।</p>
---	--	---

आजादा, स्वाधीन आरे श्रामिक आजाद



से पारित कर दिया गया था। उसी देन, सरकार ने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक, 2019 को पेश किया और पारित करवा लिया, जिसमें राज्य को विभाजित किया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगले दिन लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। यह कथित तौर पर अंविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। 6 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (3) के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें घोषणा की गई थी कि 6 अगस्त, 2019 से अनुच्छेद 70 के सभी खंड अमान्य करार दिए जाते हैं। उस अधिसूचना में केवल एक नए खंड को छोड़ दिया गया था। निडल्ड्यूसी के सभी सदस्य इस बात

एक राजनातिक दल, जो अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा कर रहा है, वह झाँठ बोल और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं करेगा? जो मुद्दा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अहम है, वह अनुच्छेद 370 नहीं है। वह विशेष दर्जा है। वह अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन का मुद्दा नहीं है। कश्मीर घाटी के अधिकांश लोग (और जम्मू और लद्दाख में भी उसे जैवन बता रहाएँ हैं) विशेष दर्जे

दलबदल का दलदल

चुना गया जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़े यात्रा देश का ध्यान खींच रही लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह सबकुछ स्वरूप लोकतंत्र के हित में नहीं है। गाहे-बगाहे देश के विभिन्न राज्यों विपक्षी दलों के विधायकों को येन-केन-प्रकारेण भाजपा में मिलाने की मुहिम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कर कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। वहीं दूसरी इससे भाजपा की राजनीतिक शैली की विश्वसनीयता को लेकर भी वाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि राजग के कई पराने सहयोगी दलों ने भाजपा से किनारा कर लिया।

वासना से शुरू हुई इस आशंका से अलगाव की कवायद हाल ही में जदयू के अलगाव के रूप में सामने आयी है। गोवा

तरह विद्यार्थी का माजपा में शामिल करने का यह खल प्रैचल दिनों पूवातर राजा, कनाटक व मध्यप्रदेश में भाँगने में आया। जिसे लोकतंत्र में जनता के विश्वास से छल ही कहा जायेगा कि जनप्रतिनिधि जनता से किसी पार्टी नाम पर वोट मांगता है और फिर दसरे राजनीतिक दल की बांह पकड़ लेता है। जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों

सहयोगियों में भी अविश्वास बढ़ा है। निस्संदेह, यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पराभव का चित्र उकेरता है। जो बताता है कि सत्ता में आने की बेंचौनी जनप्रतिनिधियों को किसी भी हद तक ले जा सकती है। फार्म उसों और गेरस्ट हाउसों में धेर कर ले जाये जाते विधायक इस दयनीय रिथति को ही उजागर करते हैं। जो राजनीतिक द्वेषों के लिए अध्यायन का विषय होता जाता है कि विषय में द्वेषों में विधायकों में बेंचौनी क्या होती है, वे यहाँ

ज्ञान के लिये जटिलता का परिवर्तन होगा। याहॅ परिवर्तन का अपेक्षा न बढ़ना न परिवर्तन का अपेक्षा न बढ़ना। यहीं जनता के विश्वास से छल कर्यों करते हैं।

तो देश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि केंद्रीय सत्ता में आये राजनीतिक दल धनबल और सरकारी एजेंसियाँ जरिये भयादोहन करके विषय को कमजोर करने का उपक्रम करते ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं रही राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि रातों-रात कैसे सरकारें गिराई जाती थीं और कि मैं राज्यपाल बदले जाते थे ताकि केंद्रीय सत्ता का निष्ठांक मार्ग स्थापित हो सके। राजनीति की इन कपथाओं

यिस्तार वर्तमान राजग सरकार के दौर में भी दिखायी दे रहा है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के जरिये विपक्षी ताओं की कमज़ोर नस पर हाथ रखा जा रहा है।

तो राजनीति के हमाम में तमाम राजनेता गाहे-बगाहे बैनकाब होते रहते हैं लेकिन विडंबना यह है कि ये राजनेता ब भाजपा में शामिल होते हैं तो पूरी तरह पाक-साफ बन जाते हैं। सवाल यह भी कि क्या सरकारी एजेंसियों को कोई तारूढ़ दल का दागी नेता नजर नहीं आता? जो विगत में विपक्ष में रहते हुए दागदार बताया जाता था। बहरहाल,

ऐसे वक्त में जब अगले आम चुनाव में समय कम ही रह गया, कांग्रेस को पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिये भीरता से विचार करना होगा। वह सोचे कि पार्टी के बड़े-बड़े दिग्गज नेता पार्टी से किनारा क्यों कर रहे हैं। कहीं पार्टी के भीतर लोकतंत्र कमजोर तो नहीं हुआ है? निसर्दाह कांग्रेस की पदयात्रा आगे बढ़ते हुए देश का ध्यान खींच रही एकजुट नहीं रख पा रही है।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारम्भ

डॉक्टर्स के कारण ही देश और प्रदेश सुरक्षित है : डॉ. राजेश्वर सिंह

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में मनाये जा रहे सेवा पथवादा के अंतर्गत रविवार को सरोजीनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने लोकबंधु राजनारायण संयुक्त स्वास्थ्य सेवा का शुभारम्भ किया। इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञों की परामर्श, जांच व देश, टीकाकरण एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर सरोजीनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि डॉक्टर्स के ही कारण देश और प्रदेश सुरक्षित है, लखनऊ के लोग सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में 36 करोड़ से अधिक कोविड डोज लाकर उत्तर प्रदेश ने राजनारायण रखा है। इसके द्वारा डॉक्टर्स भी बधाई का पात्र है। डॉ. सिंह ने बताया कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने जिस प्रकार देश की सेवा की है, उसके लिए लिए उनकी जितनी सराहना की जाए तभी कम है। अज देश में जेंडर रेशेंस सुधारा है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात 1020 हुआ है तो उसके पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी



संक्षिप्त खबरे

विद्यार्थियों की धार्मिक परीक्षा में सम्मानित हुए बच्चे

लखनऊ। श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी के 51वें वार्षिक समागम से पहले नगर के विभिन्न गुजरातों से आए विद्यार्थियों की धार्मिक परीक्षा का आयोजन हुआ। नाना के श्रीगुरु रिंग सभा गुरुद्वारा में 110 बच्चों ने इस धार्मिक परीक्षा में हिस्सा लिया। घेरावरमैन कृपाल सिंह ऐट ने बताया कि श्री सुखमनी साहिब की बाणी के साथ इसके रचयिता श्रीगुरु अर्जुन देव के जीवन पर प्रश्न पूछे गए, जिसका बच्चों ने उत्तर दिया। सभी को सांचना पुरस्कार के साथ प्रथम, द्वितीय और तीसरी एवं परीक्षियों को 21 से, 15 और 11 सौ रुपए पुरस्कार देकर समानित किया गया। कार्क्रम का आयोजन नगर विधायक ने देश और प्रदेश में जेंडर रेशेंस सुधार कराई एवं योगी आदित्यनाथ के लिए जारी कराया। जरिंदर पाल सिंह ने देश और प्रदेश में जेंडर रेशेंस से स्वास्थ्य सेवाओं का संकल्प और चिकित्सकों की मजबूत इच्छाकृती भी शामिल किया।

लम्पी वायरस से बिपटने में सरकार सजग नहीं : कांग्रेस

लखनऊ। कांग्रेस ने कहा है कि लम्पी वायरस में सरकारी आंकड़े और दावों के उल्लंघनी हकीकत में टीकाकरण की स्पीड भी काफी धीमी है। प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रियटने में की गई गलती से प्रदेश सरकार अब भी सबक नहीं ले रही है। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सबसे ज्यादा प्रदेश सरकार द्वारा देश और समाज में आये हैं। वहाँ मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, हापुर, मेरठ, शास्त्री और राजनीति वाले सामने आये हैं। अलीगढ़, राजनीति वाले के साथ ही बुलंदशहर और पूर्वांचल के भी जिलों में भी वायरस तेजी से पांच प्रसार रहा है। सरकार को इस पर तत्काल विधेय एडवाइजरी जारी करना चाहिए। वायरस से प्रभावित पशुओं को अलग रखने की व्यवस्था हो, पशुओं की मृत्यु हो जाने पर शव को खुले गंभीर रूप से आयोजित किया जाए।

गौ रक्षा महासंघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नवाचा जन्मदिन लखनऊ। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने आज यहाँ राष्ट्रीय मुख्यालय उत्तरायणी हाउस कैसरबांग के प्रागण में वश्वारोपण कर राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारतीय का जन्म दिवस मनाया। इस मोर्के पर महिला प्रदेश अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष संगीत राज, राजेश राज प्रदेश मंत्री, नमकीन चौहान एडवायोकेट प्रदेश महामंत्री, अमित शर्मा, राजू भारती, अरुण श्रीवास्तव, जानकी शिंह, सरिता त्रिपाठी, सुधा शिंह, शशुंदुला कुशवाहा, बीना वर्मा, अनीता तिवारी, नीलम मिश्रा आदि लोग उपस्थिति की व्यवस्था बनाए रखने की अपीली की ओर देखे गए। इससे पहले कार्यालय में मौजूद लोगों ने केंप काटकर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारतीय को शुभकामनाएं दी, तत्पश्चात कार्यालय प्रांगण में गौ रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारतीय एवं अपनी टीम के सदियों के साथ वश्वारोपण किया। इस मोर्के पर शुभकामनाएं देने वालों को धन्यवाद देते हुये कलीम भारतीय ने गौ रक्षा के लिये लोगों से आगे आगे की अपीली की ओर कहा कि वह सदैव गाय भाता की रक्षा के लिये तप्पर आगे रहे।

24 घण्टे डाकस्थाने में बंद रहा कुत्ता, कर्मचारियों की लापरवाही उत्तारांचल

लखनऊ। लखनऊ खीरी में पोस्ट ऑफिस की कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक आवारा कुत्ता 24 घण्टे से पोस्ट ऑफिस में कैद रहा जिससे मोर्के पर हड्डकंप मच गया। मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी कोतवाली क्षेत्र करवा की है। जब खाली पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक आवारा कुत्ता पोस्ट ऑफिस के अंदर कैद हो गया।

लखनऊ। यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने से लेकर बिना परिषट संचालन हो रहे ऑटो-टैंपो के खिलाफ रविवार को चारबांग रेलवे स्टेशन परिसर में चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई कर रहे यात्रीकर अधिकारी अनिता वर्मा ने बताया कि चैकिंग से परिसर में आ जात हैं। यात्रियों की शिकायत पर जांच की गई तो सात ऑटो-टैंपो अनाधिकृत पाए गए। इनका चालान किया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस दौरान एआरटीओ और पीटीओ आमा त्रिपाठी जौदूर रहे।

युवक की हत्या कर फेंका शव, पुलिस ने बताया हादसा तो भड़के परिजन

लखनऊ। लखनऊ के विजनौर थाना क्षेत्र के गढ़ी मवेहा गांव में युवक की हत्या कर शव फेंक दिया गया। युवक का शव सड़क के बिनारे गढ़ी में मिला। मामला लखनऊ पुलिस कमिशनरेट के मध्य जोन के विजनौर थाना क्षेत्र का है। जहाँ गांव में हत्या के बाद युवक का शव फेंका गया।

कुल मिलाकर अब तक इस मामले में दस पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। एसपी आकाश तोमर के मुताबिक लाइनमैन की हुई मौत के बीच एसपी ने विद्युत लाइनमैन के बीच एसपी को विद्युत स्टॉप कर दिया। मामले में पूछताछ के लिये थाना लाया गया था, जहाँ पूछताछ के दौरान तबियत विद्युतने पर देव को जिला अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मरण घोषित कर दिया।

उनके कारबंधु राजनारायण संयुक्त सेवा शिविर का लोग भी कम हुआ है, पहले पैदा हुए 1000 बच्चों में से 47 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे अब यह अंकड़ा घटकर 35 हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर भी कम हुआ है, इन उपलब्धियों के पास राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय के पात्र हैं। सरोजीना नगर विधायक ने देश और प्रदेश में जेंडर रेशेंस सुधार कराई एवं भी अन्य भाजपा पदाधिकारी भी उपरिथित रहे।

उन्होंने बताया कि परिजनों के आरोप पर जांच में प्रकाश में आये दस प्रदेशीयों पर कार्यवाही की गयी है। उन्होंने लोगों से अप्रदानी का अवलोकन किया गया। जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ पूछताछ के लिये थाना लाया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मरण घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि परिजनों के आरोप

